

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 30-05-25



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Friday, 30 May, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 Syllabus : GS 3 : Disaster Management	केरल सरकार ने कोच्चि जहाज दुर्घटना को राज्य आपदा घोषित किया
Page 03 Syllabus : GS 2 : Governance	एनएच-66 दुर्घटना: पीएसी ने सीएजी को प्रदर्शन ऑडिट करने का निर्देश दिया
Page 06 Syllabus : GS 2 : Social Justice	पुणे में एनडीए से महिला कैडेटों का पहला बैच स्नातक हुआ
Page 07 Syllabus : GS 2 : Social Justice	तम्बाकू की किफ़ायती उपलब्धता भारत में कैंसर महामारी को बढ़ावा दे रही है
Page 10 Syllabus : GS 2 : Indian Polity	ऑपरेशन सिंदूर में स्वायत्त युद्ध
Page 08 : Editorial Analysis: Syllabus : GS 2 : Social Justice	प्रारंभिक बचपन शिक्षा की पटकथा को फिर से लिखना

Page 01 : GS 3 : Disaster Management

24 मई, 2025 को, कंटेनर जहाज एमएससी एल्सा 3 खराब मौसम का सामना करने के बाद कोच्चि तट से 14.6 समुद्री मील दूर डूब गया। केरल सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभावों के कारण आधिकारिक तौर पर इस घटना को "राज्य-विशिष्ट आपदा" घोषित किया है।

Kerala government declares Kochi shipwreck a State disaster

The Hindu Bureau
THIRUVANANTHAPURAM

The Kerala government has declared the shipwreck that occurred 14.6 nautical miles off its coast on May 24 a "State-specific disaster".

Tinku Biswal, Principal Secretary of the State Disaster Management department, stated that the shipwreck off Kochi posed a potentially serious threat to Kerala's coast, environmentally, socially, and economically.

Ms. Biswal stated in the government order that the incident had raised serious concerns, including the potential for oil spills and drifting of debris, such as cargo containers, in the littoral waters abutting Kerala's coastline.

la's coastline.

The order permits the State Disaster Management Authority to mobilise resources, including personnel and significant sums of money from the State Disaster Response Fund (SDRF), for relief efforts.

MSC Elsa 3, which had set sail for Kochi from Vizhinjam, foundered after encountering extreme weather.

640 containers

A perilous combination of heavy seas, possible hull leakage, mechanical failure and perhaps unbalanced cargo reportedly caused the ship to list heavily and sink. The Coast Guard rescued the ship's crew, comprising 21 individuals.



Floating threat: A shipping container found washed ashore between Kodimunai and Vaniyakudi along the Tamil Nadu coastline on Thursday. SPECIAL ARRANGEMENT

The Customs department verified the ship's cargo manifesto.

It said the sunken vessel threw 640 containers, in-

cluding 12 containing hazardous incendiary material, overboard when it flipped over. Thus far, at least 54 containers have

washed ashore on the beaches of Kollam (43), Thiruvananthapuram (9), and Alappuzha (2).

Meanwhile, Revenue Mi-

nister K. Rajan said a emergency response ship from Puducherry had set sail for the sunken ship.

He further said a marine disaster management team had cordoned off waters near the shipwreck site with floating booms to prevent oil slicks from spreading.

The Indian National Centre for Ocean Information (INCOIS) has mapped areas where weathered pieces of oil from a ship, known as "tar balls or petroleum blobs", could wash up along Kerala's coastline.

In South T.N.

Meanwhile, a container from the sunken Liberian ship washed ashore between Kodimunai and Vani-

yakudi in Tamil Nadu's Coimbatore on Thursday, a day after several bags of tiny plastic pellets from the ship were found along the shores of coastal villages in the western part of Kanniyakumari district.

Since Wednesday, containers from the ship are drifting towards Kanniyakumari due to ocean currents and monsoon winds.

Kanniyakumari District Collector R. Alagumeena told *The Hindu*, "An expert team from the shipping company in Gujarat is on its way to recover the item from the shore." Revenue and police officials are providing security to the container.

EDITORIAL
» PAGE 8

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- पर्यावरणीय खतरा: जहाज़ पर 640 कंटेनर थे, जिनमें से 12 खतरनाक आग लगाने वाली सामग्री से भरे थे। तेल रिसाव, बहता हुआ मलबा और टार बॉल्स का बनना नाजुक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताएँ: किनारे पर बहकर आए कंटेनर और छोटे प्लास्टिक के छर्चे विषाक्त संपर्क, संदूषण और माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के ज़रिए तटीय समुदायों को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
- आर्थिक प्रभाव: तटीय मछली पकड़ने वाले समुदाय जोखिम में हैं। पर्यटन और बंदरगाह संचालन भी बाधित हो सकते हैं।
- प्रशासनिक प्रतिक्रिया: केरल ने धन और कर्मियों को जुटाने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत प्रावधानों का इस्तेमाल किया। तेल के दाग को फैलने से रोकने के लिए फ्लोटिंग बूम तैनात किए गए।

व्यापक निहितार्थ:

1. समुद्री बुनियादी ढाँचे की कमी:

- भारतीय शिपिंग में सुरक्षा जाँच, कार्गो संतुलन प्रोटोकॉल और मौसम की तैयारियों की पर्याप्तता पर चिंताएँ बढ़ाता है।

2. आपदा तैयारी:

- एनडीएमए ढाँचे के तहत मजबूत समुद्री आपदा प्रबंधन योजनाओं की आवश्यकता।

o राज्यों (केरल और तमिलनाडु) और केंद्रीय एजेंसियों (आईएनसीओआईएस, तटरक्षक) के बीच समन्वय अंतर-एजेंसी सहयोग में अंतराल और ताकत को उजागर करता है।

3. पर्यावरण शासन:

o खतरनाक कार्गो और माइक्रोप्लास्टिक्स से दीर्घकालिक प्रदूषण समुद्री परिवहन के लिए सख्त पर्यावरणीय मंजूरी के महत्व को रेखांकित करता है।

4. कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय पहलू:

o जहाज लाइबेरियाई ध्वज वाला था, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और भारत के अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में अधिकारों/जिम्मेदारियों के तहत मुद्दों को उठाता था।

आगे की राह:

- भारतीय जल से गुजरने वाले कार्गो जहाजों का व्यापक ऑडिट।
- खतरनाक सामग्रियों के लिए आईएमओ प्रोटोकॉल का सख्त पालन।
- उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में स्थायी समुद्री निगरानी और सफाई दल।
- ऑपरेटरों को जवाबदेह ठहराने के लिए एक समुद्री पर्यावरण क्षतिपूर्ति ढांचे का विकास।
- आपदा प्रतिक्रिया योजना में जन जागरूकता और तटीय समुदाय की भागीदारी।

निष्कर्ष:

- कोच्चि जहाज दुर्घटना भारत की समुद्री आपदा तैयारियों के लिए एक चेतावनी है। यह पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और शासन के बीच के अंतरसंबंध को स्पष्ट रूप से सामने लाता है। सक्रिय योजना, अंतर-राज्यीय समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भविष्य में ऐसी समुद्री आपदाओं को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: समुद्री दुर्घटनाएँ भारत की पर्यावरणीय और आर्थिक सुरक्षा के लिए बहुआयामी खतरा पैदा करती हैं। एमएससी एल्सा 3 घटना के संदर्भ में चर्चा करें। (150 words)

केरल के मलप्पुरम जिले में कूरियाड के पास छह लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-66 (NH-66) का एक हिस्सा ढह गया, जिससे बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा हो गई हैं। जवाब में, संसदीय लोक लेखा समिति (PAC) ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को परियोजना का निष्पादन ऑडिट करने का निर्देश दिया है।

NH-66 collapse: PAC directs CAG to do performance audit

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Days after a section of the under-construction six-lane National Highway 66 collapsed at Kooriyad in Malappuram district of Kerala, Parliament's Public Accounts Committee (PAC), headed by Congress leader K.C. Venugopal, directed the Comptroller and Auditor General (CAG) to conduct a comprehensive performance audit, scrutinising the contract terms, and the road design that led to the collapse.

As per sources, officials from both the Ministry of Road and Transport and the National Highways Authority of India (NHAI)

admitted at the meeting that the collapse was due to design flaw.

Other projects

The panel also asked the NHAI Chairman to inspect the affected stretch and review other projects in the State. It is learnt that Mr. Venugopal said there had been multiple complaints regarding construction flaws in national highway stretches across seven districts in Kerala.

Recounting his recent visit to Kooriyad, Mr. Venugopal reportedly said the road had been constructed in an area full of fields and swamps, without a strong foundation or consideration of local conditions.

मामले का महत्व:

- डिजाइन में खामी की स्वीकृति: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा एनएचआई के अधिकारियों ने स्वीकार किया कि यह पतन खराब डिजाइन योजना के कारण हुआ, खास तौर पर दलदली और खेतों वाले क्षेत्र में।
- बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में जवाबदेही: पीएसी का हस्तक्षेप बुनियादी ढांचे के विकास में कार्यकारी चूक पर संसदीय निगरानी की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।
- शिकायतों का व्यापक पैटर्न: केरल के सात जिलों में कई संरचनात्मक खामियों की रिपोर्ट राजमार्ग निर्माण में एक प्रणालीगत समस्या का संकेत देती है, न कि एक अलग घटना।

व्यापक चिंताएँ उजागर की गईं:

1. स्थानीय परिस्थितियों की उपेक्षा:

- पर्याप्त आधारभूत समर्थन के बिना दलदली क्षेत्रों में निर्माण भू-तकनीकी मूल्यांकन की कमी को दर्शाता है।
- पर्यावरण और मिट्टी की स्थितियों के साथ इंजीनियरिंग प्रथाओं को संरेखित करने में विफलता को दर्शाता है।

2. मजबूत निगरानी तंत्र की आवश्यकता:

- एनएचएआई और कार्यान्वयन ठेकेदारों द्वारा अपनाई गई गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया पर सवाल उठाता है।
- परियोजना निष्पादन के दौरान प्रभावी तृतीय-पक्ष निरीक्षणों का अभाव।

3. सार्वजनिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

- इस तरह के पतन से जीवन को खतरा होता है, कनेक्टिविटी में देरी होती है, सार्वजनिक लागत बढ़ती है और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में नागरिकों का भरोसा खत्म होता है।

4. राजकोषीय निरीक्षण और लेखापरीक्षा भूमिका:

- CAG ऑडिट के लिए PAC का निर्देश सार्वजनिक परियोजनाओं में पारदर्शिता और पैसे के मूल्य को सुनिश्चित करने में वित्तीय और प्रदर्शन लेखापरीक्षा के महत्व को रेखांकित करता है।

आगे की राह:

- सड़क अनुमोदन से पहले अनिवार्य भू-तकनीकी सर्वेक्षण।
- विभिन्न चरणों में तीसरे पक्ष की गुणवत्ता जांच को संस्थागत बनाना।
- राजमार्ग डिजाइन में आपदा लचीलापन मानदंड को मजबूत करना।
- CAG जैसे स्वतंत्र निकायों द्वारा नियमित प्रदर्शन लेखापरीक्षा।
- संवेदनशील निर्माण क्षेत्रों में स्थानीय हितधारक परामर्श को शामिल करना।

निष्कर्ष:

- NH-66 का पतन केवल एक तकनीकी विफलता नहीं है, बल्कि एक शासन चूक है। यह बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक समग्र, जवाबदेह और क्षेत्र-संवेदनशील दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। भारतमाला जैसी राष्ट्रीय योजनाओं के तहत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में बढ़ते निवेश के साथ, हर कदम पर गुणवत्ता, सुरक्षा और जवाबदेही को एकीकृत करना महत्वपूर्ण है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत में बुनियादी ढांचे की जवाबदेही सुनिश्चित करने में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की भूमिका पर चर्चा करें। हाल के उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। (250 Words)

सशस्त्र बलों में लैंगिक समावेशन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में, 17 महिला कैडेटों के पहले बैच ने 148वें एनडीए पाठ्यक्रम के भाग के रूप में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), पुणे से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। यह सुप्रीम कोर्ट के 2021 के ऐतिहासिक फैसले के मद्देनजर हुआ है, जिसने पहली बार महिलाओं के लिए एनडीए में प्रवेश खोला।

First batch of women cadets graduates from NDA in Pune

Convocation ceremony marks historic moment for women in the Indian armed forces; cadet Shriti Daksh secures first place in BA stream to win Silver Medal and Chief of Air Staff Trophy

Snehal Mutha
MUMBAI

The first batch of 17 women cadets graduated from the National Defence Academy in Pune on Thursday, marking a historic moment for women in the Indian armed forces.

At least 339 cadets were given degrees during the convocation ceremony of the 148th NDA course. The academy trains cadets for the Army, Navy, and Air Force.

Division cadet Shriti Daksh etched her name in the history books as she became the first woman cadet to receive the Silver Medal and Chief of Air Staff Trophy for securing first rank in the BA stream.

Lucky Kumar received the Chief of Army Staff Trophy for topping the B.Sc. stream, and battalion cadet Captain Prince Kumar Kushwaha lifted the Chief of Naval Staff Trophy for topping the computer science branch.

Academy cadet Captain Udayveer Singh Negi



Primed to serve: Cadets after the 148th convocation ceremony held at the National Defence Academy in Pune on Thursday. EMMANUAL YOGINI

emerged topper in the B.Tech. stream.

The Vice-Chancellor of the Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Poonam Tandon, who was the chief guest at the event, referred to the excellent performance of women cadets while addressing the graduands: "Service has no gender and your presence is historic."

NDA Commandant Vice-Admiral Gurcharan Singh hailed the historic event, calling the woman cadets "hope". He further said achieving name and fame in their service to the nation will be their "guru-dakshina" to the NDA.

SC verdict

After a Supreme Court verdict in 2021, the Union Pu-

blic Service Commission (UPSC) permitted women to apply for the NDA examination for the first time.

The cadets were given B.Sc., BA, and B.Tech. degrees from the Delhi-based Jawaharlal Nehru University (JNU).

The passing out parade of the 148th course of the academy will be held on Friday.

आयोजन का महत्व:

1. रक्षा क्षेत्र में लैंगिक बाधाओं को तोड़ना:

- दशकों तक एनडीए केवल पुरुषों का संस्थान था। महिला कैडेटों का स्नातक होना भारत की रक्षा नीति और लैंगिक प्रतिनिधित्व में एक परिवर्तनकारी बदलाव को दर्शाता है।

2. न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से समानता को बनाए रखना:

- सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने अनिवार्य किया कि महिलाओं को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जो समानता, गैर-भेदभाव और अनुच्छेद 14 के संवैधानिक मूल्यों के साथ संरेखित हों।

3. योग्यता का प्रतीक:

- कैडेट श्रीति दक्ष, जिन्होंने बीए स्टीम में प्रथम रैंक हासिल की, यह साबित करती हैं कि समावेशन मानकों से समझौता नहीं करता है; बल्कि, यह विविधता और योग्यता को बढ़ाता है।

व्यापक निहितार्थ:

1. सशस्त्र बलों में संस्थागत परिवर्तन:

- एनडीए में महिलाओं को शामिल करने से शुरुआती चरणों से ही समावेशी प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास को बढ़ावा मिलता है।
- यह बलों को लैंगिक समानता के लिए बुनियादी ढांचे, मानसिकता और कमांड संस्कृति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

2. लैंगिक समानता के लिए प्रेरणा:

- यह भारत भर की युवा लड़कियों के लिए पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका निभाने की आकांक्षा रखने के लिए एक शक्तिशाली संकेत के रूप में कार्य करता है।

3. नागरिक-सैन्य सुधार:

- लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ व्यापक नागरिक-सैन्य संरेखण को दर्शाता है, जहाँ न्यायालय के नेतृत्व वाली नीति परिवर्तन संस्थागत परिवर्तन को प्रभावित करती है।

4. सहायक उपायों की आवश्यकता:

- प्रेरण से परे, समान कैरियर प्रगति, पोस्टिंग, कमांड भूमिकाओं और लिंग-संवेदनशील कार्य वातावरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

- यह मील का पत्थर औपचारिकता से अधिक है - यह बदलते समय का प्रतीक है जहाँ लिंग अब क्षमता को परिभाषित नहीं करता है। एनडीए 148 की महिला कैडेट न केवल स्नातक हैं, बल्कि भारत की रक्षा तैयारियों और लैंगिक समानता ढांचे में एक नए युग की पथप्रदर्शक हैं। हालाँकि, असली परीक्षा संस्थागत स्वीकृति, लड़ाकू भूमिकाओं में समान अवसर और बिना किसी पूर्वाग्रह के कैरियर की प्रगति में है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: सेवा में कोई लिंग नहीं होता। एनडीए में महिला कैडेटों को शामिल करने के आलोक में, भारतीय सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता प्राप्त करने में हुई प्रगति और चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। (250 Words)

Page 07 : GS 2 : Social Justice

कराधान और विनियमन के माध्यम से तम्बाकू के उपयोग को कम करने में वैश्विक प्रगति के बावजूद, भारत में तम्बाकू अत्यधिक किफ़ायती और सुलभ बना हुआ है। यह किफ़ायतीपन धूम्रपान और धूम्रपान रहित तम्बाकू से संबंधित कैंसर में वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है, जिसके स्वास्थ्य और आर्थिक परिणाम महत्वपूर्ण हैं।

Tobacco affordability fuelling cancer epidemic in India

Unlike in other countries where higher prices have deterred smoking, prices remain low in India; tobacco affordability undermines the World Health Organization's MPOWER framework and weakens control, hindering efforts to reduce tobacco-related cancers; implementing robust policies are the need of the hour to curb tobacco use

WORLD NO TOBACCO DAY

Vid Karmarkar

Take a walk around any Indian office, and you're likely to spot some employees gathered outside, sipping tea and smoking a cigarette. Sandeep, a young marketing professional, calls such "sutta (smoking) breaks" a creative escape. "It's time to take a break from work stress and make connections. The chai-sutta break is where ideas flow as freely as the smoke." But for many non-smokers, this comes at a cost – involuntary exposure to second-hand smoke.

According to GATS data, nearly 42% of men and 14% of women in India use tobacco. Home to 70% of the world's smokeless tobacco (SLT) users, SLT is preferred over smoked tobacco in the country. In smoked tobacco, the bidi is favoured over cigarettes, especially in rural and low-income groups. Despite the preference for bidis, India has seen the largest increase in the market share of cigarettes globally.

Rajesh, a shopkeeper in Mulshi, a village near Pune, says, "Bidis are what people here can afford. Cigarettes are for the city folks. But now even in villages, people want to try cigarettes because they think it's modern."

Both SLT and smoked tobacco drastically increase cancer risk, particularly for lung, head, neck, stomach, and pancreatic cancers. "My uncle chewed tobacco for years," said Sumita, a homemaker from Maharashtra. "He passed away from mouth cancer, and we didn't realise how dangerous it was until it was too late," she says.

India ranks first globally in male cancer incidence and mortality rates. Among tobacco-related cancers in males, lung cancer leads globally, while in India, lip and oral cancers top the list, followed by lung cancer. "Every time I see someone with a gutkha (which is banned in India) pouch in their pocket, I feel like warning them," says Manish, a college student whose father died of oral cancer.

Along with the health burden, tobacco use imposed an economic cost of ₹1.77 lakh crore (1.04% of India's GDP) in 2017-2018. Smoking accounted for 74% of these costs, while SLT use made up 26%. With tobacco use on the rise, both health and economic costs are projected to increase. Rajiv, who quit smoking after a cancer scare, says: "I never realised the financial toll until I saw the hospital bills. Smoking doesn't just cost you money – it costs you your life and the lives of those who depend on you."



Call to action: People taking part in a rally against smoking on the occasion of World No Tobacco Day which is observed annually on May 31. K. MURALI KUMAR

India faces a dual challenge of significant health and economic burdens from tobacco-related cancers and the complexities of lung cancer screening in a tuberculosis-endemic country. This underscores the urgent need for evidence-based anti-tobacco policies as a primary prevention strategy. However, the tobacco industry's influence – through policy interference, pricing tactics to maintain affordability, targeted marketing, dense tobacco shop networks, and a lack of political will – ensures widespread tobacco accessibility.

"The fact that a bidi costs less than a cup of tea is a tragedy," says Ashok, a retired clerk. "When I was younger, I didn't think twice about buying a bidi. Now I see how cheap tobacco ruins lives." Taxation is a critical yet underutilised tool in reducing tobacco use. Despite the proposed GST increase to 35%, it falls short of the World Health Organization's recommendation of taxing tobacco at 75% of its MRP to effectively deter use. Even with the steep increase in tobacco tax, its impact decreases if consumers' income increases significantly.

Unlike in many countries where higher prices have curbed smoking, rising incomes in India – especially among the 450 million middle class – have outpaced tax hikes. With more purchasing power, tobacco remains affordable. The 2024

Union Budget's unchanged tobacco taxes worsened the issue, enabling "undershifting," where manufacturers absorb tax hikes to grow their markets.

Unit pricing

A key factor in tobacco affordability is its unit pricing. A pack of bidis has a median price of ₹12 but can be found for as little as ₹5. Similarly, smokeless tobacco products have a median price of ₹5, with some being sold for as low as ₹1. Shankar, a daily wage labourer and cancer patient says he could afford to buy a few packs every day. While cigarette packs have a median price of ₹95, cheaper options are available for as low as ₹5. Sonia, a college student, says, "Cigarettes are so cheap that they're easy to buy. The government needs to make it harder for people like us to afford them."

To enhance affordability, cigarettes are often sold as single sticks – a practice banned in 88 countries but not in India. Priced at approximately ₹15, single sticks become easily affordable and bypass graphic health warnings. Research shows that 87% of Indian cigarette vendors sell single sticks, frequently operating near tea stalls, reinforcing the widespread "chai-sutta" culture.

In India where a significant proportion of the population earns ₹170-480 per day, along with the addictive potential of

tobacco, makes the current tobacco pricing affordable to fulfill their cravings.

Tobacco affordability undermines the WHO's MPOWER framework and weakens tobacco control, hindering efforts to reduce tobacco-related cancers. Reducing tobacco use is vital for cutting cancer incidence. Implementing robust anti-tobacco policies can be effective in curbing tobacco use.

Regular tax hikes that outpace income growth can make tobacco products unaffordable, discouraging their use. Additionally, banning single-stick sales can reinforce health warnings and curb impulse purchases. Further, allocating tobacco tax revenue towards public health initiatives, such as cancer screenings in underserved areas, can have a significant impact. Enforcing plain packaging with prominent health warnings can also reduce tobacco's appeal, while restricting sales near tea stalls can help break the 'chai-sutta' association. Robust enforcement, through regular inspections and penalties, is essential to uphold these regulations.

(Dr. Vid Karmarkar is a social entrepreneur, researcher, writer and advocate of advancing equitable cancer care and global health. He is also the founder of the Cansava Foundation, a registered nonprofit organisation. vid.karmarkar@gmail.com)

THE GIST

India ranks first globally in male cancer incidence and mortality rates. Among tobacco-related cancers in males, lung cancer leads globally, while in India, lip and oral cancers top the list, followed by lung cancer.

Along with the health burden, tobacco use imposed an economic cost of ₹1.77 lakh crore (1.04% of India's GDP) in 2017-2018. Smoking accounted for 74% of these costs, while SLT use made up 26%.

India faces a dual challenge of significant health and economic burdens from tobacco-related cancers and the complexities of lung cancer screening in a tuberculosis-endemic country. This underscores the urgent need for evidence-based anti-tobacco policies as a primary prevention strategy.

मुख्य चिंताएँ:

1. उपयोग का उच्च प्रचलन:

- भारत में 42% पुरुष और 14% महिला तम्बाकू उपयोगकर्ता हैं।
- वैश्विक धूम्ररहित तम्बाकू (एसएलटी) उपयोगकर्ताओं में से 70% से अधिक भारत में रहते हैं।
- सांस्कृतिक सामान्यीकरण (जैसे, "चाय-सुट्टा" ब्रेक) नियमित उपयोग में योगदान देता है।

2. तम्बाकू उत्पादों की सामर्थ्य:

- बीड़ी, गुटखा और सिगरेट मात्र ₹1 से ₹15 तक में बिकते हैं, जिससे वे दिहाड़ी मजदूरों के लिए भी सस्ते हो जाते हैं।
- 88 देशों में प्रतिबंधित सिंगल-स्टिक की बिक्री भारत में जारी है, जो ग्राफिक स्वास्थ्य चेतावनियों को दरकिनार कर रही है।

3. सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव:

- तम्बाकू से संबंधित कारणों से पुरुष कैंसर मृत्यु दर में भारत विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है।
- भारत में होंठ और मुंह के कैंसर सबसे आम हैं, इसके बाद फेफड़ों का कैंसर है।

4. आर्थिक बोझ:

- तंबाकू से संबंधित बीमारियों से भारत को सालाना 1.77 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 1.04%) का नुकसान होता है।
- इसका एक बड़ा हिस्सा अस्पताल में भर्ती होने, उत्पादकता में कमी और दीर्घकालिक देखभाल के कारण होता है।

नियंत्रण प्रयासों को कमजोर करने वाले प्रणालीगत मुद्दे:

- अपर्याप्त कराधान: वर्तमान कर स्तर (लगभग 35%) डब्ल्यूएचओ की 75% एमआरपी अनुशंसा से कम है।
 - तम्बाकू उद्योग द्वारा नीतिगत हस्तक्षेप, विशेष रूप से अंडरशिफ्टिंग (कर वृद्धि को अवशोषित करना) जैसी मूल्य निर्धारण रणनीतियों के माध्यम से।
- खराब विनियमन प्रवर्तन: स्कूलों, चाय की दुकानों और सार्वजनिक स्थानों के पास आसान पहुँच।
- कम राजनीतिक इच्छाशक्ति: हाल के बजटों में तंबाकू कर में न्यूनतम संशोधन तत्परता की कमी को दर्शाता है।

सिफारिशें और नीतिगत कार्रवाई:

1. वहनीयता को कम करने के लिए आय वृद्धि से अधिक नियमित कर वृद्धि।
2. पैकेजिंग-आधारित स्वास्थ्य चेतावनियाँ दिखाई देने के लिए सिंगल-स्टिक सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध।
3. ग्राफिक स्वास्थ्य संदेशों के साथ सादे पैकेजिंग को लागू करें।
4. आदतन उपभोग पैटर्न को तोड़ने के लिए स्कूलों और चाय की दुकानों के पास बिक्री को प्रतिबंधित करें।
5. कैंसर स्क्रीनिंग और समाप्ति कार्यक्रमों की ओर तम्बाकू कर राजस्व को पुनर्निर्देशित करें।
6. उल्लंघन के लिए दंड और नियमित निगरानी सहित मजबूत कानूनी प्रवर्तन।

निष्कर्ष:

- भारत का तम्बाकू संकट केवल एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या नहीं है, यह एक शासन और आर्थिक चुनौती है। साक्ष्य और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के बावजूद, भारत आक्रामक तम्बाकू विरोधी नीतियों को लागू करने में पिछड़ रहा है। अपर्याप्त विनियमन द्वारा समर्थित वहनीयता, कैंसर महामारी को बढ़ावा दे रही है जो असमान रूप से गरीबों को प्रभावित करती है। कराधान, कानून, सार्वजनिक जागरूकता और संस्थागत जवाबदेही को मिलाकर एक बहुआयामी दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: तम्बाकू की वहनीयता एक नीतिगत विफलता है जो भारत में कैंसर के बोझ को बढ़ाती है। WHO MPOWER ढांचे के संदर्भ में चर्चा करें। (250 words)

Page 10: GS 3 : Internal Security & Science & Technology

पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिशोध में भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर दक्षिण एशियाई युद्ध में एक ऐतिहासिक घटना थी — जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों द्वारा मानव रहित हवाई प्रणालियों (यूएएस) और स्वायत्त प्लेटफार्मों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। इस संघर्ष ने एल्गोरिदम-संचालित युद्ध के एक नए प्रतिमान के उद्भव को चिह्नित किया, जहां सशस्त्र ड्रोन, घूमते हुए हथियार, झुंड के हमले और डिजिटल निरोध ने पारंपरिक युद्ध की जगह ले ली।

Autonomous warfare in Operation Sindoor

In the recent India-Pakistan war, over four days of hostilities, both sides effectively rewrote their rules of engagement, ushering in a 'new normal' of airborne deterrence without pilots, but with autonomous platforms, armed drones and loitering munitions

FULL CONTEXT

Rahul Bedi

Launched in early May, in retaliation to the April 22 Pahalgam terror attack, Operation Sindoor marks a historic milestone, in which Unmanned Aerial Systems (UAS) played a primary role in direct military combat between two nuclear-armed neighbours, signalling an uncharted era of drone-centric warfare in South Asia.

Over four days of hostilities, both sides effectively rewrote their rules of engagement, ushering in a 'new normal' of airborne deterrence without pilots, but with autonomous platforms, armed drones and loitering munitions, all operating below the threshold of a full-scale war, and shaping a calibrated, escalation-managed conflict.

In the 48 hours preceding Operation Sindoor, Israeli Heron MK-II and indigenously designed TAPAS-BH-201/Rustom-II-Medium-Altitude Long-Endurance (MALE) Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) Unmanned Aerial Vehicles (UAS) are believed to have flown deep into Pakistani airspace to gather electronic and signals intelligence and thermal signatures of suspected Islamist terror camps.

Thereafter, from May 7 onwards, after the Indian Air Force (IAF) attacked nine targets inside Pakistan, both sides employed a broad spectrum of UAS – from ISR UAVs to armed drones, kamikaze loitering munitions, electronic decoys and quadcopters – as dual-purpose tools for real-time intelligence gathering and precision strikes. And as this drone war intensified, both countries sought to dominate the battlespace through persistent aerial surveillance by mapping out enemy air defences, missile batteries, command centres, troop clusters and logistical nodes. Decoy drones too were widely employed to spoof radars, 'bait' air defence systems and exhaust interceptors, minimising risk to manned assets, before ceasefire ensued on May 10.

India's array of aerial systems

In the intervening period, India claimed to have downed some 600 Pakistani drones, releasing intercepted footage and wreckage to reinforce its assertions in a high-stakes information war, paralleling the kinetic exchanges. Pakistan, in turn, alleged that 300-400 Indian drones had unsuccessfully targeted its military and strategic infrastructure, before being shot down. India has neither confirmed nor denied these avowals, citing Operation Sindoor's enduring operational status for its silence.

Open-source intelligence and drone-tracking data, meanwhile, revealed that India's offensive against Pakistan featured a diverse UAS inventory. It was spearheaded by indigenously developed loitering munitions like the GPS-guided Nagastri-1 and Israeli-origin Harop drones, capable of autonomously homing in on enemy radar systems.

To overwhelm Pakistan's air defences, India also deployed swarm drone formations developed jointly by the Defence Research and Development Organisation and private contractors to create radar clutter, trigger premature defensive responses and saturate surveillance networks. Priority targets included ammunition depots, Surface-to-Air Missile (SAM) batteries, radar sites, and forward operating bases.

The strikes were delivered in carefully



New war: A soldier looks at a drone at the Akhnoor sector near the LoC in Jammu on May 19, 2019.

sequenced waves. Initial sorties deployed decoy drones and electronic warfare payloads to saturate radar coverage and provoke early, albeit futile SAM launches. These were followed by precision loitering munitions and armed UAVs, guided in real-time by Heron MK IIs and TAPAS-BH-201 Rustom-IIs. Quadcopters and micro-UAVs played a critical role in relaying live ISR feeds and target acquisition data via the Army's Integrated Battle Management System (IBMS) to forward units, ensuring dynamic targeting and reaction.

Notably, media reports claimed that India's drone strikes disrupted a cricket match in Rawalpindi, forcing a stadium evacuation due to air defence alarms. Another significant Harop strike, reportedly destroyed a Chinese-supplied HQ-9 air defence system near Lahore, delivering both a psychological blow and a strategic setback to Pakistan's layered air defence shield.

Consequently, military analysts noted that India's overwhelming use of varied UAS to deliver calibrated, cross-border strikes without risking manned aircraft, represented the emerging regional model of deterrence. They said it also visibly showcased India's growing competence in autonomous, cost-effective, and networked warfare, demonstrating a significant shift in the balance of aerial power in South Asia.

Pakistan's retaliation

Pakistan, for its part, in its reactive Operation Buryan-um-Marsoos (wall of lead), deployed a range of UAS, including its indigenously developed Shahpar (feather)-II MALE UAVs, armed Burraq (lightning) drones, Turkish-origin Bayraktar TB2s, and Chinese-supplied CH-9 and Wing Loong II platforms. These assets were complemented by GH-901 and WS-43 loitering munitions from China and domestically produced kamikaze drones, launched at multiple targets across a 1,500-kilometre expanse, stretching from Kashmir in the north to Bhuj in the west.

While the Shahpar-IIs, TB2s, and Wing Loong IIs primarily conducted ISR

missions – streaming real-time imagery of Indian troop concentrations, artillery positions, and logistics depots – Pakistan's loitering munitions targeted radar stations, forward operating bases and critical Army and IAF command nodes in the northern and western sectors. However, these attacks were effectively neutralised by India's robust, multi-tiered air defence grid, inflicting minimal or no damage at all.

Strategic urban and military infrastructure hubs – including Jammu, Pathankot and Amritsar in Punjab, Bikaner and Jaipur in Rajasthan, and Bhuj in Gujarat – too were frequently targeted. But despite the density of these assaults, India's integrated air defence network – comprising layered radar coverage, SAM batteries, automated threat-response mechanisms, and upgraded Cold War-era legacy platforms and systems – mitigated damage, preventing disruption.

India's multi-layer air defence system Pakistan repeatedly sought to probe and bring to heel India's Integrated Air Command and Control System (IACCS) – its air defence nerve centre – by launching drones via varied routes, altitudes and diverse timings, to disrupt its communication nodes and forward-deployed command centres, albeit unsuccessfully. The IACCS fuses surveillance inputs from ground-based radars, airborne early warning and control platforms, satellites, and other sensors into a centralised but distributed command-and-control network. It integrates with SAM systems and fighter aircraft, enabling the rapid detection, tracking, and interception of low-altitude threats, including UAS. Its built-in mechanisms ensured continuity of operations, even if any individual nodes were damaged, jammed or destroyed.

Pakistan attempted to overload the IACCS's radar coverage, confuse response loops, and expose vulnerabilities for follow-on drone or missile strikes. However, military officials confirmed the IACCS's core network remained intact,

with all and any temporary disruptions swiftly mitigated through alternate data links and pre-positioned mobile radars. Analysts further noted the system's 'mesh' architecture allowed seamless failovers when nodes were hit, with satellite uplinks and mobile platforms sustaining full situational awareness. The IACCS also displayed its Directed Energy Weapons (DEWs) capability in which high-powered lasers or microwaves, via a real-time network, detected, tracked and neutralised airborne threats like drones speedily.

Complementing the IACCS at the tactical level was the Akashteer (Sky Arrow) air defence control and reporting system, developed by Bharat Electronics Limited, which provided a digitised command layer for Army Air Defence units, enabling seamless coordination between sensor units and weapon platforms. Designed to rapidly disseminate targeting data and manage low-level threats – including UAVs – it ensured that frontline SAM units could engage targets with minimal delay, even under electronic warfare or communication stress.

The accompanying air defence shield was built around a layered architecture combining retrofitted legacy Low-Level Air Defence (LLAD) systems with advanced missile platforms in an unparalleled innovative mix that remains a hallmark of the Indian military's improvisation.

A new kind of war

The domestic Akash and Akash-NG (New Generation) missile system provided medium-range coverage, while the long-range Barak-8, jointly developed with Israel, defended high-value assets and strategic nodes from aircraft, drones, and ballistic/cruise missiles. These were all backed by Russia's Almaz-Antey S-400 'Triumf' self-propelled surface-to-air missile system – renamed Suvidha Chakra – one of the world's best, of which India had acquired five units for \$5.5 billion in October 2018 and, so far, taken delivery of three.

All these systems were centrally integrated through the IACCS, enabling coordinated, real-time responses and full-spectrum aerial threat mitigation.

In conclusion, Operation Sindoor was not merely a skirmish; it was a seismic shift in which two nuclear-armed rivals stepped into the age of autonomous warfare, where deterrence is digital, and dominance is algorithmic. And as the smoke subsides, one truth remains: the next war will not begin with a soldier's charge, but with the silent whir of drones in the sky.

Rahul Bedi is a veteran journalist based in New Delhi and Chandigarh specialising in military, defence and security matters.

THE GIST

Open-source intelligence and drone-tracking data, meanwhile, revealed that India's offensive against Pakistan featured a diverse UAS inventory.

Pakistan repeatedly sought to probe and bring to heel India's Integrated Air Command and Control System (IACCS) – its air defence nerve centre – by launching drones via varied routes, altitudes and diverse timings, to disrupt its communication nodes and forward-deployed command centres, albeit unsuccessfully.

Operation Sindoor was not merely a skirmish; it was a seismic shift in which two nuclear-armed rivals stepped into the age of autonomous warfare, where deterrence is digital, and dominance is algorithmic.

ऑपरेशन सिंदूर की मुख्य विशेषताएं:

भारत की रणनीति:

- यूएवी की बड़े पैमाने पर तैनाती: इजरायली हेरॉन एमके-11, भारतीय तापस-बीएच-201, रुस्तम-11, नागास्त्र-1 और हारोप ड्रोन।
- ड्रोन संरचनाओं ने पाकिस्तानी रडार और एसएएम को दबा दिया।
- इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ड्रोन का इस्तेमाल दुश्मन की रक्षा प्रणालियों को धोखा देने और उन्हें नष्ट करने के लिए किया गया।
- मिसाइल बैटरियों, रडार स्टेशनों और कमांड सेंटर जैसी महत्वपूर्ण पाकिस्तानी संपत्तियों को निशाना बनाया।
- 600 पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया, जिससे बेहतर हवाई निगरानी स्थापित हुई।

पाकिस्तान का जवाबी हमला - ऑपरेशन बनयान-उम-मर्सूस:

- शाहपार-11, बुराक ड्रोन, चीनी सीएच-4, विंग लूंग II और तुर्की से बेराकटर टीबी2 का इस्तेमाल किया गया।
- भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों के खिलाफ CH-901 और WS-43 लोइटरिंग म्यूनिसन तैनात किए गए।
- सटीकता की कमी थी और भारत की बहु-परत वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा काफी हद तक बेअसर कर दिया गया।

भारत का रक्षा बुनियादी ढांचा:

- **बहु-परत वायु रक्षा प्रणाली:**
- IACCS (एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली): भारत की वायु रक्षा का मूल, AI-आधारित खतरे की प्रतिक्रिया, वास्तविक समय रडार संलयन और निर्बाध विफलता में सक्षम।
- विरासत LLAD सिस्टम: उन्नत शीत युद्ध-युग के सोवियत AA प्लेटफॉर्म का अभिनव रूप से उपयोग किया गया।
- आधुनिक मिसाइलें: आकाश, आकाश-एनजी, बराक-8, और एस-400 'सुदर्शन चक्र' को आईएसीसीएस के माध्यम से एकीकृत किया गया।

○ ड्रोन को बेअसर करने के लिए लेजर और माइक्रोवेव तकनीक जैसे निर्देशित ऊर्जा हथियार (DEWs)।

- आकाश प्रणाली: सेना-स्तरीय वास्तविक समय वायु रक्षा समन्वय परत।

रणनीतिक निहितार्थ:

1. ड्रोन युद्ध परिपक्व हो गया है: ऑपरेशन सिंदूर दक्षिण एशिया में स्वायत्त हथियारों को मुख्यधारा में लाने का प्रतीक है।
2. डिजिटल प्रतिरोध: युद्ध जनशक्ति-आधारित से एआई-नेटवर्क कमांड सेंटर और स्वचालित प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहा है।
3. लागत-प्रभावी शक्ति प्रक्षेपण: यूएवी सीमाओं के पार कम जोखिम, उच्च प्रभाव वाली स्ट्राइक क्षमता प्रदान करते हैं।
4. वृद्धि नियंत्रण: पूर्ण पैमाने पर युद्ध से कम कार्रवाई को बनाए रखा, जो वृद्धि प्रबंधन के नए सिद्धांत को दर्शाता है।

सबक और भविष्य का दृष्टिकोण:

- भारत को रणनीतिक स्वायत्तता के लिए स्वदेशी ड्रोन उत्पादन (जैसे, नागास्त्र-1) को बढ़ाना चाहिए।
- साइबर सुरक्षा और एआई-आधारित खतरे का पता लगाना राष्ट्रीय रक्षा में अगला मोर्चा बन जाएगा।
- स्वायत्त युद्ध के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है, विशेष रूप से परमाणु पड़ोस में।
- सीमावर्ती राज्यों को स्थानीय वायु रक्षा, ड्रोन जैमिंग सिस्टम और त्वरित प्रतिक्रिया टीमों से लैस होना चाहिए।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: आधुनिक संघर्षों में एआई-सक्षम स्वायत्त हथियारों के उपयोग से उत्पन्न नैतिक, रणनीतिक और परिचालन संबंधी चुनौतियाँ क्या हैं? (250 words)

Page : 08 Editorial Analysis

Rewriting the script of early childhood education

“Some kids win the lottery at birth; far too many don’t – and most people struggle to catch up,” said the Nobel Laureate Prof. James Heckman. This holds true for India as well where its employment problem is partly a consequence of this “lottery of birth”. A child born in India has a one-in-five chance of being born into poverty, affecting their health, nutrition, learning and earning potential. Yet, there is a way to beat these odds. From the decision by Uttar Pradesh to hire 11,000 dedicated Early Childhood Care and Education educators for Balvatikas to Odisha launching Shishu Vatikas and Jaduipedi Kits, States in India are showing the way.

The Heckman curve was a powerful economic model that provided a simple yet profound insight – of the relationship between age and the rate of return on investments in human capital. Heckman found that every dollar invested in early childhood education yields a return that ranges from \$7 to \$12, with lasting impacts: children who receive quality early education are four times more likely to have higher earnings and three times more likely to own a home as adults. By age five, many gaps in outcomes – such as earning potential and quality of life – are already evident. Children often struggle throughout life if motivation and learning habits are not nurtured early.

Learning outcomes

Yet, India’s ECE system faces three major challenges. First, children are not receiving sufficient instructional time. Nearly 5.5 crore children between ages three to six are enrolled in 14 lakh operational Anganwadis and 56,000 government pre-primary schools. However, Anganwadi workers spend only 38 minutes per



Shaveta Sharma-Kukreja

is the Chief Executive Officer and Managing Director at Central Square Foundation



Luis Miranda

is the Chairperson and Co-founder of the Indian School of Public Policy and the Chairman of the Centre for Civil Society

Strategic investments in early childhood education and engaging parents will help young learners

day on preschool instruction, which is far short of the scheduled two hours, and only 9% of pre-primary schools have a dedicated ECE teacher. We are planting trees without the right care to help them grow. The effects are reflected in learning outcomes. The India Early Childhood Education Impact Study found that only 15% of pre-primary children could match basic objects, a skill essential for letter recognition in Class one. Similarly, only 30% could identify larger and smaller numbers, which are foundational for arithmetic. As a result, children often start formal schooling without the skills they need, with many bypassing essential ECE years entirely: 2% of three-year-olds, 5.1% of four-year-olds, and nearly one-fourth of five-year-olds are enrolled directly in Class one.

The issue of resources, engaging parents

Second, the thoughtful optimisation of resources for early childhood education remains a challenge. The Government of India spends only ₹1,263 a child annually on ECE compared to ₹37,000 a student on school education – largely on producing teaching-learning materials that are often underused. There simply are not enough teachers to implement these resources, and there is a lack of oversight – one supervisor is responsible for monitoring 282 Anganwadis. To improve oversight, we need targeted funding to hire more supervisors and dedicated ECE teachers. These measures, though modest, promise high returns.

Uttar Pradesh has now moved ahead on the hiring of nearly 11,000 ECE educators for Balvatikas in all districts. The State also organised a six-day residential training programme for 50 master trainers from 13 districts to train them on ECE pedagogy. Odisha

has taken the decision to open Shishu Vatikas in all government schools to make children in the age group five to six school ready.

While increased funding would lead to immediate improvements, sustaining these gains depends on engaging parents, and here lies the third challenge. Most parents care deeply about their children’s education but may lack guidance on supporting early learning. Empowering parents with simple, effective ECE practices can make a significant difference. For instance, providing worksheets or encouraging their participation in ECE centre activities can deepen their involvement.

In Madhya Pradesh, the monthly Bal Choupal programme engages with parents directly by showing them the importance of play-based learning. With smartphone access nearly universal, parental engagement can be further strengthened through WhatsApp or EdTech apps, allowing parents to support their children’s development.

In perspective

Reversing these odds may seem like an uphill battle, but with targeted funding and increased parental involvement, we can provide our children with the foundation they deserve.

By 2047, over a billion Indians will enter the global workforce, presenting an unprecedented opportunity to reshape India’s role in the world economy. Strategic investments in ECE and engaging parents in their children’s learning journey could help 200 million Indians escape the lottery of birth and give today’s young learners the chance to become tomorrow’s leaders. This is a critical pathway to realising India’s vision of becoming a true Vishwa Guru, empowering generations to come.

Paper 02 : सामाजिक न्याय

UPSC Mains Practice Question : ECE में सार्वजनिक निवेश से मानव पूंजी पर सबसे अधिक लाभ मिलता है। भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए हेकमैन वक्र की प्रासंगिकता की जाँच करें। (250 words)

संदर्भ:

- लगातार असमानता और सीखने के अंतराल की पृष्ठभूमि में, शावेता शर्मा-कुकरेजा का लेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि गरीबी के चक्र को तोड़ने के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा (ईसीई) कितनी महत्वपूर्ण है। लेख में हेकमैन कर्व का संदर्भ दिया गया है, जो मजबूत मानव पूंजी बनाने के लिए शुरुआती वर्षों में निवेश को आर्थिक रूप से उचित ठहराता है।

पहचाने गए प्रमुख मुद्दे:

1. ईसीई केंद्रों में कम शिक्षण समय:

- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनुशंसित 2 घंटों के बजाय प्रीस्कूल शिक्षा पर केवल 38 मिनट/दिन खर्च करते हैं।
- केवल 9% प्री-प्राइमरी स्कूलों में समर्पित ईसीई शिक्षक हैं।
- बुनियादी अंतराल स्पष्ट हैं क्योंकि केवल 15% बुनियादी मिलान कार्य कर सकते हैं और केवल 30% कक्षा। शुरू करने तक बुनियादी संख्यात्मकता को समझते हैं।

2. असमान और अपर्याप्त वित्त पोषण:

- ईसीई को स्कूली शिक्षा के लिए ₹37,000 की तुलना में प्रति बच्चा/वर्ष केवल ₹1,263 मिलते हैं।
- उच्च पर्यवेक्षक-से-केंद्र अनुपात (1:282) खराब प्रशासनिक क्षमता को दर्शाता है।

3. माता-पिता की सहभागिता में कमी:

- माता-पिता चिंतित हैं, लेकिन उनमें प्रारंभिक शिक्षा का समर्थन करने के लिए जागरूकता और उपकरणों की कमी है।
- व्हाट्सएप या एडटेक ऐप जैसी कम लागत वाली तकनीक का कम उपयोग किया जाता है।

सकारात्मक विकास:

- उत्तर प्रदेश 11,000 समर्पित ECE शिक्षकों को नियुक्त कर रहा है और आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है।
- ओडिशा ने स्कूल की तैयारी बढ़ाने के लिए शिशु वाटिका और जादूईपेडी किट लॉन्च की है।
- मध्य प्रदेश का बाल चौपाल कार्यक्रम खेल-आधारित शिक्षा को समझने में माता-पिता को सीधे जोड़कर आशाजनक है।

निहितार्थ:

- आधारभूत शिक्षा सीधे भविष्य की उत्पादकता और कमाई की क्षमता को प्रभावित करती है।
- ECE में छूटे अवसर भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को कमजोर करते हैं।
- प्रारंभिक क्षमता और बाद के परिणामों के बीच के अंतर को नीति प्राथमिकता, बजट पुनर्वितरण और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से व्यवस्थित सुधार की आवश्यकता है।

अनुशंसाएँ:

1. समर्पित ECE कार्यबल को संस्थागत बनाएँ: सभी राज्यों में 3-6 आयु वर्ग के लिए विशेष रूप से शिक्षकों की भर्ती करें और उन्हें प्रशिक्षित करें।
2. प्रति-बाल निधि में वृद्धि: उचित ट्रेकिंग और उपयोग के साथ बजट आवंटन में ECE को प्राथमिकता दें।
3. निरीक्षण और जवाबदेही बढ़ाएँ: पर्यवेक्षक क्षमता में सुधार करें और आंगनवाड़ी के कामकाज की वास्तविक समय की निगरानी करें।
4. माता-पिता की भागीदारी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएँ: माता-पिता के प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और निगरानी के लिए व्हाट्सएप/एडटेक टूल का उपयोग करें।
5. प्री-प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य करें: सार्वभौमिक कवरेज और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए RTE अधिनियम के तहत 3 साल की ECE शामिल करें।

निष्कर्ष:

- 2047 तक वैश्विक आर्थिक नेता बनने की भारत की आकांक्षा काफी हद तक इसकी मानव पूंजी की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, जो बचपन की शिक्षा से शुरू होती है। जल्दी निवेश करके, फ्रंटलाइन शिक्षकों का समर्थन करके और माता-पिता को सशक्त बनाकर, भारत अंतर-पीढ़ीगत गरीबी के चक्र को तोड़ सकता है और अपने बच्चों को पनपने के लिए तैयार कर सकता है। प्रारंभिक हस्तक्षेप केवल एक सामाजिक अनिवार्यता नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय विकास रणनीति है।